

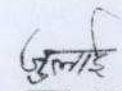
प्रेषक,

अमित सिन्हा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड, देहरादून

गृह अनुभाग-1


देहरादून: दिनांक:- २ जून, 2012

विषय:- 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्थान सरियापानी में आपदा प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण केन्द्र के भवन का निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या: डीजी-दो-130-2007, दिनांक 02 मार्च, 2012 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के स्थान सरियापानी में आपदा प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण केन्द्र के भवन निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था 'ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग', जनपद अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध कराये गये ₹ 2.49 लाख के आगणन का तकनीकी परीक्षणोपरान्त ₹ 2.16 लाख पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये निर्माण कार्य के प्रथम चरण हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 2.16 लाख(रूपये दो लाख सोलह हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

3- कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

4- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

5- एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

6- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो.नि.वि. द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

कमश....2

7— निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लायी जाए।

8— आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

9— निर्माण कार्य तथा इस हेतु सामग्री क्य में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली (Uttarakhand Procurement Rules), 2008 के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण इकाई से M.O.U निष्पादित किया जाय जिसकी प्रति शासन को भी उपलब्ध करायी जाय।

10— स्वीकृत धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए किया जाय तथा व्यय उन्ही मदों में किया जाय जिस हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

11— निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए सम्बन्धित निर्माण संस्था उत्तरदायी होगी। कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल एवं तदविषयक समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12— यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित की जायेगी।

13— वित्त विभाग के वैबसाईट पर आवश्यक धनराशि आवंटित कर दी गई है। आवंटन शीट संलग्न है।

14— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय आयोजनागत, 800-अन्य व्यय, 0103-13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण के मानक मद 24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

15— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या:-13/P/xxvii(5)/12, दिनांक 06 जून, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,

(अमित सिन्हा)
अपर सचिव

कमश.....03

संख्या एवं दिनांक तदैवः—

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तदनुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
3. निदेशक, कोषागार, 25 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- ✓5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र(एन.आई.सी.) सचिवालय परिसर देहरादून।
6. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, प्रखण्ड अल्मोड़ा।
7. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग—5, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

मुकुल
(जे. पी. जोशी)
संयुक्त सचिव